आर्थिक समीक्षा
2019-20

खण्ड 1

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली–110001
ई–मेल: cordecdn-dea@nic.in
जनवरी, 2020

विषय सूची

अध्याय सं.	पृष्ठ सं.	अध्याय का नाम
1		**अर्थ संपदा सृजनः विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका**
	2	अर्थ सृजन का महत्व
	6	खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से अर्थ सृजन
	9	संपत्ति सृजन के लिए उपकरण
	14	इस शताब्दी के पहले के वर्षो में विश्वास का टूटना
2		**जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन**
	28	उद्यमिता एवं जीडीपी
	35	उद्यमी गतिविधि के निर्धारक तत्व
	38	तेज रफ्तार उद्यमिता एवं धन सृजन हेतु नीति निर्धारण
3		**व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद**
	43	बाजार समर्थक, रचनात्मक विनाश एवं संपत्ति सृजन
	52	पक्षपातवाद और वैभव विनाश
	55	नीलामियों के माध्यम से आबंटन की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आबंटन
	60	जोखिम रहित प्रतिफल - जानबूझ कर चूक का मामला
	63	नीतिगत सुझाव
4		**बाजार की अनदेखीः जब अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से लाभ की बजाय नुकसान होता है।**
	72	आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी ए), 1955
	78	ईसीए के अंतर्गत औषधि मूल्य नियंत्रण
	82	खाद्यान्न बाजारों (मंडियों) में सरकारी हस्तक्षेप
	88	ऋण माफियां
	93	सरकारी हस्तक्षेप को कम करनें के लिए अपेक्षित विधायी बदलाव
5		**नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार-सृजन और विकास**
	102	चीन की तुलना में भारत का निर्यात में निम्न-निष्पादन
	109	ग्लोबल वेल्यू चेन में भागीदारी से लाभप्राप्त करना।
	110	रोजगार के सृजन हेतु कौन से उद्योगों में भारत को विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए?
	116	प्रवेश का पैटर्न
	119	रोजगार एवं जीडीपी का संभावित लाभ
	121	क्या व्यापार समझौता लाभकारी है?
	124	भावी परिदृश्य
6		**भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य**
	128	परिचय
	130	वैश्विक तुलना
	132	विनिर्माण में विधिक जटिलता एवं सांविधिक अनुपालन की आवश्यकता
	134	व्यवसाय शुरू करनाः रेस्टोरेंट चलाने में नियामक बाधांए
	136	निर्माण अनुज्ञा

137 व्यापार के बड़े पैमाने को प्राप्त करना
137 सीमापार व्यापार
139 विशिष्ट खंडों में संभारतंत्र में भारत के निष्पादन का केस अध्ययन
147 निष्कर्ष

7 **बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती: एक समीक्षा**
156 बैंकिंग संरचना: राष्ट्रीयकरण से अब तक
157 राष्ट्रीयकरण के लाभ
163 पीएसबी की दक्षता बढ़ाना: भावी परिदृश्य
176 निष्कर्ष

8 **एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता**
183 आवर्ती जोखिम (रोल ओवर रिस्क) का संकल्पनात्मक ढांचा
186 एचएफसी तथा खुदरा-एनबीएफसी के बीच अंतर
193 परिसंपत्ति वित्तीय भंगुरता आकलन हेतु निदान
199 नीतिगत विवक्षाएं

9 **निजीकरण और धन सृजन**
206 निजीकरण का प्रभाव: फर्म स्तर का विश्लेषण
224 भावी परिदृश्य

10 **क्या भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है? नहीं।**
231 परिचय
233 क्या जीडीपी का गलत आकलन किया गया है?
251 एक निदानकारी विश्लेषण
257 निष्कर्ष

11 **थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र**
260 प्रस्तावना
263 थाली की कीमतें
267 थाली की वहनीयता
272 थाली के घटकों के मूल्यों का रूझान
274 थाली स्फीति
276 थाली की कीमतों में परिवर्तनशीलता
285 निष्कर्ष

आभारोक्ति

आर्थिक समीक्षा 2019-20 मिलजुल कर किए गए कार्य एवं परस्पर सहयोग का परिणाम है। यह आर्थिक समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन तथा माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की मूल्यवान टिप्पणियों तथा उनकी अंर्तदृष्टि से अत्यंत लाभान्वित हुई है। यह समीक्षा जिन अधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से भी लाभान्वित हुई है उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-श्री राजीव कुमार, अतनु चक्रवर्ती, अजय भूषण पांडे, डॉ॰ टी.वी. सोमनाथन, तुहिन पांडे, अरविंद श्रीवास्तव एवं विशाल शर्मा शामिल हैं।

इस समीक्षा को तैयार करने में आर्थिक प्रभाग के जिन कार्मिकों का योगदान उल्लेखनीय है उनमें: संजीव सान्याल, सुष्मिता दासगुप्ता, अरुण कुमार, राजीव मिश्रा, राजश्री रे, ए. सृजा, सुरभि जैन, अश्विनी लाल, अथिरा एस बाबू, अभिषेक आचार्य, जितेन्द्र सिंह, रजनी रंजन, अविनाश दाश, सिंधुमन्निकल थंकप्पन, प्रेरणा जोशी, धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा अरोड़ा, दिव्या शर्मा, एम. राहुल, रवि रंजन, तुलसीप्रिया राजकुमारी, शमीम आरा, गुरविंदर कौर, जे.डी. वैशंपायन, आर्या बालन कुमारी, संजना काद्यान, अमित श्योरन, श्रेया बजाज, मनोज कुमार मिश्रा, सुभाष चंद, रियाज अहमद खान, मो. आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पाईन, नरेंद्र जेना, श्रीवत्स कुमार परिदा, मृत्युंजय कुमार, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, अर्पिता वायकेरे, महिमा, अंकुर गुप्ता, अर्जुन वर्मा, लविशा अरोड़ा, सोनाली चौधरी, कविशा गुप्ता, तीर्थंकर मंडल, हर्ष मीनावत, रघुवीर राघव, एस. रामकृष्णन और सत्येंद्र किशोर शमिल हैं।

यह समीक्षा जिन अधिकारियों की मूल्यवान टिप्पणियों एवं उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारियों से लाभान्वित हुई है उनमें विशेषकर श्री आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष, भारतीय गुणवत्ता परिषद्, श्री चेतक सीतापति, परियोजना प्रबन्धक, रूद्रनील चट्टोपाध्याय, परियोजना प्रबन्धक, हेत्वी मारवीय, प्रशिक्षु, (क्यूसीआई), श्री एच नागराज, वेलंकनी इलेक्ट्रानिक्स गरीमा धीर तथा श्री अरुण कुमार झा, महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् शामिल हैं।

महत्वपूर्ण जानकारियों एवं आर्थिक समीक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा हेतु आर्थिक समीक्षा दल प्रोफेसर के॰ वैद्यनाथन का आभार व्यक्त करता है। साथ ही यह दल अजित पाई, अमियतोष पूर्णानंदम, आनंद नंदकुमार, अन्नपूर्ण सिंह, सी वीरामणि, दीप मुखर्जी, दीपा मणि, एजाज ग़नी, गौतम छाओछरिया, हर्षिणी शंकर, जेफरसन अब्रहम, महेश नंदुरकर, एन प्रभाला, नीलकंठ मिश्रा, नितिन भसीन, पीयूष चौरसिया, प्रांजल शर्मा, प्रसन्ना तंत्री, राजदीप शर्मा, रम्या कृष्णा, रवि अंशुमान, समीर सिंह जैनी, शास्वत आलोक, शिव दीक्षित, सुनील शंघाई तथा यक्षुप चोपड़ा सदृश विद्वनों द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण जानकारियों एवं टिप्पणियों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों एवं संगठनों ने अपने संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कई मंत्रालयों ने मुझसे सीधा संपर्क कर मेरे समक्ष प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई। आर्थिक समीक्षा उनके मूल्यवान समय, कार्य और योगदान के लिए कृतज्ञ है। आर्थिक कार्य विभाग के मीरा स्वरूप, के. राजारमन, राजकुमार तिवारी, रविन्दर कुमार, जसबीर सिंह, अमित कुमार, सुनील दत्त, रोहित, संजय कुमार पंडिता, साधना शर्मा, अरूण गुलाटी, सुशील शर्मा, मनीष पंवार, मुन्ना शाह, सुरेश कुमार, जोध सिंह तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार कार्यालय के अन्य कर्मचारियों एवं सदस्यों द्वारा कुशल प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया गया। समीक्षा के हिन्दी भाषान्तरण में सहयोग के लिए अनुराधा मित्रा, सचिव, राजभाषा विभाग व मंजुला सक्सेना, उप सचिव, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। समीक्षा का हिन्दी अनुवाद अत्यंत कम समय में निहारिका सिंह, सन्तोष मिश्रा, ओमप्रकाश त्रिपाठी, अर्चना सिंह, अनिता कुमारी, बबीता, लिजी थॉमस, झोन्टू मंडल, शैफाली, पवित्र जायसवाल, अंकुर भटनागर, हितेष कुमार गुप्ता, वीना, सुखदेव तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के ओमप्रकाश सिंह, मुरारी लाल गुप्ता, जगत सिंह रोहिल्ला, जनवारियुस तिर्की, जय वीर, डॉ. गौतम शर्मा, मनीष भटनागर, अजय कुमार चौधरी, अनुप शॉ, विजय कुमार, रामाश्रय, डॉ. सुरेश कुमार यादव, ध्रुव नारायण आजाद, डॉ. आनंद प्रकाश यादव, सचिन कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार साव, राघवेन्द्र पाण्डेय और जी.के. डावर द्वारा किया गया। इस समीक्षा खंड का हिन्दी संपादन प्रोफेसर बी.एस. बागला, डॉ. अब्दुल रहीम अंसारी और डॉ. लोकेंद्र कुमावत द्वारा किया गया। हिंदी टंकण कार्य कमलेश तक्खी, कुसुम लता, कल्याणी बासुमतारी, विजय कुमार कोष्टा, सुरेश चंद, धर्मवीर, संजय प्रसाद द्वारा किया गया। समीक्षा के आवरण पृष्ठ का डिजाइन इंडिया ब्रैंड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस समीक्षा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मुद्रण कार्य चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड द्वारा किया गया।

अंत में, आर्थिक समीक्षा कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिवार जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय तो दिया ही, साथ ही इस समीक्षा को तैयार करने में अपना निरंतर भावनात्मक सहयोग एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया। आर्थिक समीक्षा में समर्पित सहयोगियों के लिए निस्संदेह उनके परिवार शक्ति के मूक स्तंभ रहे हैं।

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

प्राक्कथन

सन 1976 में एडम स्मिथ द्वारा रचित आधुनिक अर्थशास्त्र का महाप्रबंध ग्रंथ का बड़ा रोचक नाम रखा गया-''ऐन इनक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन''। वर्ष 2019 में जब भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और वर्ष 2055 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, स्मिथ द्वारा उठाए गए आधारभूत प्रश्नों में से इस प्रश्न की ओर वापस जाना उपयुक्त प्रतीत होता है कि ''किसी राष्ट्र की संपदा और समृद्धि के मूल कारण क्या हैं? इस आर्थिक समीक्षा 2019-20 मे ऐसी नीतियों का फ्रेमवर्क तैयार करने का विनम्र प्रयास किया गया है जो भारत में संपदा की वृद्धि का कारण बन सकें। इस स्तर पर यह समीक्षा विशेषरूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वर्ष 2025 तक + 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है-एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण जो-जैसा कि स्मिथ ने उल्लेख किया था ''सार्वभौम समृद्धि जिसका विस्तार समाज के सबसे निचले तबके तक है'', का सृजन करे।

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 के अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस बात पर जोर दिया कि समृद्धि का वितरण तभी हो सकता है जब समृद्धि का सृजन किया जाए। अत: भारत के सम्पन्नता सृजकों के प्रति संदेह और असम्मान की भावना अविवेकी है। समाजवाद के साथ भारत का ''वास्ता'' को देखते हुए संपदा सृजन के लाभों के बारे में संशय कोई इत्तफाक नहीं है। इस संदर्भ में team@ecosurvey2019-20 ने आर्थिक विचारण और आर्थिक नीति निर्माण दोनों ही स्तरों पर बाजार अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभों के संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने का प्रयास किया है।

इस समीक्षा में उल्लेख है कि सम्पदा सृजन के विचार का मूल कॉटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर थिरूवल्लुवर के ''थिरूकुरल'' की प्राचीन और समृद्ध भारतीय परंपरा में निहित है, जिसमें नैतिक रूप में सम्पदा सृजन के कार्य को आदर्श मानवीय व्यवसाय मानने पर बल दिया गया है। इस समीक्षा में प्राचीन साहित्य और समकालीन साक्ष्य का उपयोग यह दर्शाने के लिए दिया गया है कि समाजवाद के साथ भारत का जुड़ाव-सहस्त्रवर्षीय इतिहास में कुछ दशकों के क्षणिक अवधि का है जो मानक के रूप में बाजार के अदृश्य हाथ पर विश्वास एक अपवाद है। मेंडीसन (2007) ने ऐतिहासिक साक्ष्य रूप में उल्लेख किया है कि भारत अर्थव्यवस्था के ज्ञात इतिहास के तीन चौथाई से अधिक समय तक प्रभावी वैश्विक आर्थिक ताकत रहा है। यह प्रभुत्व भारत की सुगठित अर्थव्यवस्था का परिणाम है न कि कोई संयोग है। यह समीक्षा प्राचीन व्यवस्था को व्यस्त करने वाले साहित्य के आधार पर यह दर्शाने के लिए तैयार की गयी है कि बाजार के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को जब विश्वास द्वारा समर्थन मिलता है तो इस प्रकार आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त की जा सकती है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत को अपनी जड़ों की ओर लौटने के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि समकालीन साक्ष्यों को प्रस्तुत करती है। वैश्विक वित्तीय संकट की घटनाएं और भारतीय वित्तीय क्षेत्र की चुनौतियां अप्रत्याशित आर्थिक समस्याओं के सहारे के लिए विश्वास के सहारे की आवश्यकता के साक्ष्य प्रस्तुत करती है। विश्वास को जन मानस के हित में प्रयोग किए जाने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस समीक्षा में लोगों के हितों में वृद्धि के लिए भी कुछ सुझाव हैं। इस प्रकार सम्पन्नता सृजन के लिए इस समीक्षा की अवधारणा प्राचीन और नवीन संश्लेषण प्रस्तुत करती है जोकि प्राचीन भारतीय परम्परा और समकालीन साक्ष्य का संयोजित रूप है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे बैंकों के संबंध में फिन टेक का सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इस समीक्षा में संश्लेषण के साथ ही साथ नए 100 रुपए के नोट और पुराने 100 रु. के नोट दोनों की महक समाहित है।

इस समीक्षा में संपदा सृजन के क्रम को आगे बढ़ाने हेतु बहुत से लीवर दिए गए हैं: भारत के विभिन्न जिलों में नई फर्म चालू करने में यथा प्रदर्शित जमीनी स्तर पर उद्यमिता, व्यापार अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना जो प्रो-क्रोनी की वृत्तिभोगी निजी हितों की पक्षधर नीतियों के विरूद्ध सम्पन्नता लाने के लिए प्रतियोगी बाजार की शक्तियों को उजागर करती है। समीक्षा में यह विषय आया है कि स्वस्थ बाजारवाद पद्धति द्वारा तैयार किए गए आंदोलन ने स्थैतिक सहयोगवाद पद्धति की बजाए अधिक धनार्जन किया है।

यह उल्लेख किया जाए कि समीक्षा दोनों पद्धतियों के विपरीत है; दलील व्यक्ति या प्रतिष्ठान केंद्रित नहीं है। इसकी बजाए, इसमें उन नीतियों को समाप्त करने की दलील दी गई है जो सरकारी हस्तक्षेप जहां पर यह आवश्यक नहीं है, के माध्यम से बाजारों का कमतर मूल्यांकन करती है; श्रम-गहन उद्योग निर्यात पर बल देने के लिए ''एसेंबल इन इंडिया'' को ''मेक इन इंडिया'' में समाकलित करती है तथा बड़े पैमाने पर जॉब सृजित करती है; भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र में प्रभावी ढंग से वृद्धि करती हैं तथा आभासी बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य की देखरेख करती हैं; दक्षता को बढ़ाने के लिए निजीकरण का प्रयोग करती हैं। अदृश्य हाथ के सहयोग से विश्वास की उम्मीद के साथ समीक्षा में सतर्क साक्ष्य दिया गया है कि जीडीपी वृद्धि के प्राक्कलन पर विश्वास किया जा सकता है।

आर्थिक नीति की लिखतों के रूप में व्यावहारिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए आर्थिक समीक्षा 2018-19 के सामान्य उद्देश्य को जारी रखने हुए तथा मानव व्यवहार के बारे में अवलोकन करने के आसान आंकड़ों के रूप में आर्थिक समीक्षा 2019-20 में वस्तु, जिसका सामना पुरूष या महिला प्रतिदिन करती है-खाने की प्लेट अर्थात् थाली, का प्रयोग करके सामान्य व्यक्ति को अर्थशास्त्र से जोड़ने का प्रयास है।

हमने समीक्षा को दो खण्डों में प्रस्तुत करने की लोकप्रिय परंपरा को जारी रखा है। खण्ड 1, इसमें उन विचारों को प्रस्तुत किया है जो ''आर्थिक आजादी एवं धन सृजन' को संपुटित करते हैं, इसमें विश्वसनीय नीति निर्माण के लिए हाल ही के आर्थिक विकास कार्यों के आर्थिक विश्लेषण पर आधारित साक्ष्य दिए गए हैं। खण्ड II में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हुए हाल ही के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है तथा यह संगत सांख्यिकीय तालिकाओं एवं डाटा से समर्थित है। क्षेत्र की मौजूदा स्थिति एवं नीतियों के लिए रैडी रेकनर का कार्य करेगा।

इस आर्थिक समीक्षा के अस्तित्व और लोकप्रियता का श्रेय, भारत सरकार के सभी कार्यालयों, विभागों, आर्थिक सेवा के अधिकारियों के विलक्षण संसाधन आधार, शोधकर्त्ताओं, सलाहकारों, सरकारी और बाह्य दोनों क्षेत्रों के प्रबुद्ध मंडल/विशेषज्ञ दल के बहुमूल्य परामर्श तथा आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग के सभी अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों को जाता है। इस समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने, इसे समझने और इसके बारे में चिंतन करने की दिशा में अपरिहार्य मार्गदर्शक बनने की अभिलाषा पर खरा उतरने का निश्छल प्रयास किया गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए गहनता से विचार-विमर्श करने में team@ecosurvey2019-20 का वैयक्तिक परितोषण हमारे अनंतिम पंचाट को प्रस्तुत करता है। हमे पूरी आशा है कि सुधी पाठकगण भी उसी आशावाद का अनुभव करेंगे जिसके प्रयोजनार्थ हमने इस समीक्षा को प्रस्तुत किया है।

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संकेताक्षर

3 एस.एल.एस.	3 स्तरीय न्यूनतम वर्ग
ए.ए.आई.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ए.सी.एन.ए.एस.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति
ए.डी.	मृत्यु उपरांत
ए.ई.ओ.	प्राधिकृत आर्थिक संचालक
ए.ई.पी.	समवेत अंतिम उत्पाद
ए.ई.आर.ए.	विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ए.एल.एम	आस्ति-देयता प्रबंधन समस्याएं
ए.एस.ई.ए.एन. (आसियान)	दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ
ए.यू.एम.	प्रबंधाधीन परिसंपत्तियां
बी.ए.सी.एल.	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
बी.ई.सी.	व्यापक आर्थिक श्रेणियां
बी.एल.ई.एल.(भेल)	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. (बिम्सटेक)	बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
बी.पी.सी.एल.	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
बी.एस.ई	मुबंई शेयर बाजार (बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज)
बी.एस.ई.एस.	मुंबई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति
बी.टी.	ब्रिटिश टेलीकॉम
सी.ए.जी.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
सी.ए.जी.आर.	घातांकी वार्षिक वृद्धि दर
सी.ए.आर.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात
सी.बी.आई.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सी.बी.आई.सी	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सी.बी.यू.	पूर्णत: निर्मित इकाई
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति
सी.सी.आई.एल.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
सी.सी.टी.	सशर्त नकद अंतरण
सी.डी.	परितर्वनीय डिबेंचर
सी.जी.डी.	विनिवेश का कोर समूह
सी.आई.बी.आई.एल. (सिबिल)	ऋण आसूचना ब्यूरो लिमिटेड
सी.आई.पी.	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
सी.के.डी.	पूर्णत: घटी कीमतें
सी.एम.सी.एल.	कम्प्यूटर प्रबंध निगम लिमिटेड
सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक
सी.पी.	वाणिज्यिक पत्र
सी.पी.एस.ई.	केन्द्रीय लोक सेवा उपक्रम
सी.आर.आई.एल.सी.	बड़े कोर्पोरेट्स पर सूचनाओं का केन्द्रीय भण्ड़ार
सी.एस.ओ.	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
सी.वी.सी.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डी.सी.ए.	उपभोक्ता मामले विभाग
डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
डी.एच.एफ.एल.	दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
डी.आई.सी.जी.सी.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डी.आई.डी.	अंतरों-में-अंतर
डी.आई.आई.	घरेलू संस्थागत निवेशक
डी.आई.पी.ए.एम.(दीपम)	निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग
डी.पी.सी.ओ.	औषधि कीमतें नियंत्रण आदेश
डी.आर.टी.	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डी.वी.ए.	घरेलू मूल्यवर्धन
ई.सी.ए.	अनिवार्य वस्तु अधिनियम
ई.आई.एल.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ई-एन.ए.एम.	इलैक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
ई.ओ.डी.बी.	कारोबारी सुगमता
ई.एस.ओ.पी.	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
ई.टी.एफ.	विनिमय व्यापारित निधि
ई.यू.	यूरोपीय संघ
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम

एफ.डी.आई.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफ. ई.	स्थाई प्रभाव
एफ.ई.एम.ए. (फेमा)	विदेशी विनिमय प्रबधंन अधिनियम
एफ.आई.आई.	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफ.टी.ए.	मुक्त व्यापार करार
एफ.टी.सी.	संघीय व्यापार आयोग
एफ.वाई.	वित्त वर्ष
जी.डी.डी.पी.	सकल घरेलू जिला उत्पाद
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.सैक	सरकारी प्रतिभूतियां
जी.एस.एफ.सी.	गुजरात राज्य उर्वरक और रसायन
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
जी.वी.सी.	वैश्विक मूल्य श्रंखलाएं
एच.सी.आई.	भारतीय होटल निगम
एच.ई.एल.पी. (हैल्प)	हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति
एच.एफ.सी.	आवास वित्त कंपनी
एच.एल.ए.जी.	उच्च स्तरीय सलाहकारी समूह
एच.पी.सी.एल.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लिमिटेड
एच.टी.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स
आई.बी.बी.आई.	भारतीय दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
आई.बी.सी.	दिवालियापन एवं शोधन अक्षयता संहिता
आई.बी.पी.	इंडो ब्राइट पेट्रोलियम
आई.सी.डी.	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आई.सी.आई.सी.आई.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
आई.डी.बी.आई.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आई.ई.एफ.	आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
आई.आई.पी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आई.एल.एफ.एस.	अवसंरचना लीजिंग और वित्तीय सेवाएं
आई.एम.एफ.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आई.-ओ.	आगम-निर्गम
आई.ओ.सी.	भारतीय तेल निगम
आई.पी.सी.एल.	भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड
आई.पी.ओ.	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आई.आर.डी.ए.आई.	भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण
आई.एस.आई.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान
आई.एस.डब्ल्यू.जी.एन.ए.	राष्ट्रीय लेखाओं पर अंतर-सचिवालीय कार्यदल
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.टी.सी.	अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
आई.टी.डी.सी.	भारतीय पर्यटन विकास निगम
जे.ए.एम.	जन धन-आधार मोबाइल
जे.एन.पी.टी.	जवाहरलाल नेहरू पार्ट ट्रस्ट
एल.डी.एम.एफ.एस.	नकदी ऋण म्यूचयल फण्ड
एम.ए.पी.ई.	अधिकतम अनुमत्य पश्च-विनिर्माण व्यय
एम.बी.ए.	व्यवसाय प्रशासन निष्णात
एम.सी.ए.	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
एम.एफ.आई.	लघु वित्त संस्थान
एम.एफ.आई.एल.	मॉडर्न फुड इंडस्ट्रिज लिमिटेड
एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम.एम.टी.सी.एल.	खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड
एम.एन.ई.	बहु-राष्ट्रीय उद्यम
एम.पी.सी.	सीमांत उपभोग प्रवृत्ति
एम.पी.सी.ई.	मासिक प्रति व्यक्ति व्यय
एम.आर.टी.पी.	एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.टी.एन.एल.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एम.यू.एल.	मारूति उद्योग लिमिटेड
एन.बी.एफ.सी.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एन.सी.डी.	अपरिवर्तनीय डिबेंचर
एन.ई.एल.पी.	नवीन अन्वेषण लाइसेंसिग नीति
एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एन.आई.टी.आई. (नीति)	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
एन.एल.ई.एम.	अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची
एन.एम.डी.सी.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

एन.एम.एस.ए.	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन
एन.पी.	नेटवर्क उत्पाद
एन.पी.ए.	अनर्जक परिसंपत्ति
एन.पी.बी.	नए निजी बैंक
एन.पी.पी.ए.	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्रधिकरण
एन.आर.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय रेस्त्रां संघ
एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
एन.टी.सी.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम
ओ.ई.सी.डी.	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओ.एन.जी.सी.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
ओ.पी.बी.	पुराने निजी बैंक
ओपेक्स अनुपात	प्रचालन व्यय अनुपात
पी. एंड सी.	भाग एवं घटक
पी.ए.टी.	कर पश्चात लाभ
पी.डी.पी.एस.	भावांतर भुगतान योजना
पी.डी.एस.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पी.के.वी.वाई.	परंपरागत कृषि विकास योजना
पी.एल.एफ.एस.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पी.एम.-आशा	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
पी.एम.एफ.बी.वाई.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी.एम.जे.डी.वाई.	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पी.पी.एस.एस.	निजी प्रापण और स्टॉकिस्ट स्कीम
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पी.एस.एफ.	मूल्य स्थिरीकरण कोष
पी.एस.एस्क.	मूल्य समर्थन स्कीम
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.सी.ई.पी.	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी
आर.ई.सी.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आर.ओ.ए.	आस्तियों पर परिलाभ
आर.ओ.ई.	इक्विटी पर परिलाभ
आर.पी.टी.	संबंधित पक्ष के लेन-देन
एस.ए.एफ.टी.ए.(साफ्टा)	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र
एस.ए.आई.एल.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
एस.बी.आई.	भारतीय स्टेट बैंक
एस.सी.आई.	भारतीय नौवहन निगम
एस.डी.जी.	संधारणीय विकास लक्ष्य
एस.ई.बी.आई.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एस.ई.सी.	प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग
एस.एच.आर.यू.जी.	भारत के सामाजिक-आर्थिक उच्च-विभेदन ग्रामीण-शहरी भौगोलिक डाटासेट
एस.आई.सी.ए.	रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम
एस.आई.डी.बी.आई.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एस.आई.टी.सी.	मानक अंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण
एस.के.डी.	आधी कीमतें
एस.एम.ई.एस.	लघु और मध्यम आकारीय उद्यम
एस.एन.ए.	राष्ट्रीय लेखा प्रणाली
टी.-बिल	खजाना बिल
टी.एफ.पी.	कुल घटक उत्पादकता
टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
यू.एन.	संयुक्त राष्ट्र
यू.एन.आई.डी.ओ. (यूनिडो)	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
यू.एन.एस.सी.	संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग
यू.एस.ए.	संयुक्त राज्य अमेरिका
यू.एस.डी.	संयुक्त राज्य डॉलर
डब्ल्यू.सी.ओ.	विश्व सीमा शुल्क संगठन
डब्ल्यू.डी.आई.	विश्व विकास संकेतक
डब्ल्यू.आई.पी.ओ.	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
वाई.ओ.वाई.	वर्ष-दर-वर्ष